web : www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक-सेहत-विज्ञान-फीचर

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 11 मई 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-218

हिंद महासागर में भारत और फ्रांस की नेवी का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास

नई दिल्ली। भारत और फ्रांस ने शुक्रवार को हिंद महासागर में अपना सबसे बड़ा नौसैन्य युद्धाभ्यास किया। दरअसल, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर के शिपिंग लेन्स पर दुनियाभर की नजरें हैं। गौरतलब है कि भारत और फ्रांस, चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव तथा दक्षिण चीन सागर में तनाव पैदा करने वाले इसके क्षेत्रीय दावों को लेकर चिंतित हैं। फ्रांस के बेड़े (जिसमें उसका एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है) की कमान संभाल रहे रियर ऐडमिरल ऑलिवियर लेबास ने कहा, 'हमें लगता है कि हम इस क्षेत्र में ज्यादा स्थिरता ला सकते हैं, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और जिसमें विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय कारोबार को लेकर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है।' एशिया और यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच ज्यादातर कारोबार (खासतौर से तेल) समुद्र के जरिए होता है। इतना ही नहीं, समुद्र अपने तेल और गैस फील्ड्स को लेकर भी काफी समृद्ध है। भारत के गोवा राज्य के तट पर 17वें सालाना युद्धाभ्यास में भाग लेने वाला करीब 42,000 टन का 'चार्ल्स डि गॉले' कुल 12 युद्धपोतों और पनडुब्बियों में से एक है। दोनों देशों के छह-छह युद्धपोत और पनडुब्बियां इसमें भाग ले रहे हैं। फ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि यह युद्धाभ्यास 2001 में शुरू हुए इस अभियान का अब तक का सबसे व्यापक अभ्यास है। हिंद महासागर में भारत का पारंपरिक दबदबा चीन के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। चीन ने शिपिंग लेन्स के पास क्षेत्र में युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती भी की है। इसके अलावा 'बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव' के जरिए चीन ने कमर्शल इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है। क्षेत्र में फ्रेंच मेरीटाइम फोर्सेज के हेड रियर ऐडमिरल डिडिएर मालटरे ने कहा कि हिंद महासागर में चीन आक्रामक देश नहीं है। उन्होंने कहा, आप चीन के आसपास समुद्र में जो देखते हैं- द्वीपों पर उसके दावे, हिंद महासागर में आप नहीं देखते हैं।% दरअसल, फ्रेंच अधिकारी का इशारा दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को लेकर कई पड़ोसी देशों के साथ उपजे विवादों पर है। टॉप अफसर ने कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा नए सिल्क रोड ट्रेड रूट्स का निर्माण, जिसमें हिंद महासागर भी शामिल है, वास्तव में एक रणनीति है जो मुख्य रूप से आर्थिक और शायद दोहरे उद्देश्य को लेकर है। हालांकि मालटरे ने यह साफ नहीं किया कि दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है। उन्होंने यह जरूर कहा कि अगले 10 से 15 वर्षों में ऐसे हालात बन सकते हैं जिससे तनाव पैदा हो सकते हैं, हां चीन सागर की तरह बड़े निश्चित रूप से नहीं होंगे।

महत्वपूर्ण एवं खास

स्कूली वैन पलटने से 20 बच्चे घायल

औरैया (आरएनएस)। औरैया के बिधूना क्षेत्र में गुरुवार को एक स्कूल वैन के पलटने से 20 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। अछल्दा रोड़ पर सराय प्रथम के पैट्रोल पम्प के पास सुबह यह हादसा उस समय हुआ जब स्टेयरिंग फेल होने से चालक ने वैन से नियंत्रण खो दिया और वाहन पलट गया। हादसे में घायल बच्चों को उपचार के लिये सरकारी एवं निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी और पुलिस के जवानों ने घायल बच्चों की मदद की। पुलिस के अनुसार वैन में लगभग 65 बच्चे सवार थे। वैन चालक मौके से भाग जाने में सफल रहा। बच्चों के मुताबिक चार दिन पहले भी बस का स्टेयरिंग फेल हुआ था जिसके बावजूद विद्यालय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अभिभावकों का विद्यालय प्रशासन पर आरोप है कि बस में भूसे की तरह बच्चों को भरा जाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आज खुलेंगे तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट

रुद्रप्रयाग (आरएनएस)। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शुक्रवार दोपहर 12 बजे भक्तों के दर्शनार्थ खुलेंगे। बीकेटीसी द्वारा इसकी तैयारियां कर दी गई है। इधर डोली गुरुवार को शाम चोपता पहुंची। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डा् हरीश गौड़ ने बताया कि तृतीय केदार तुंगनाथ की डोली चोपता पहुंची। शुक्रवार सुबह पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। डोली के चोपता पहुंचने पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार नौटियाल, प्रबंधक प्रकाश पुरोहित, पूर्व मंदिर अधिकारी भूपेन्द्र मैठाणी, भगवती प्रसाद मैठाणी, लंबोदर मैठाणी, मठापति रामप्रसाद मैठाणी आदि मौजूद थे।

पूर्व राष्ट्रपति टेमर ने किया आत्मसमर्पण

रियो डी जेनेरियो। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति एवं भ्रष्टाचार के आरोपी मिशेल टेमर ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। टेमर को भ्रष्टाचार के आरोपों में मार्च के अंत में गिरफ्तार किया गया था और पांच दिन जेल रहने के बाद वह जमानत पर रिहा हुए थे, शाम को उनकी जमानत को रद्द कर आत्मसमर्पण के लिए एक दिन का समय दिया गया था। टेमर पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र एंग्रा 3 के निर्माण में रिश्वत लेने सहित, भ्रष्टाचार, गबन, हवाला कारोबार और आपराधिक साजिश जैसे आरोप है।

गोपनीयता भंग होने पर मतदानकर्मियों को दिया नोटिस

बीकानेर (आरएनएस)। राजस्थान में बीकानेर के जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने मतदान केंद्र की गोपनीयता भंग करने पर मतदानकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गौतम ने मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी रमेश सिहाड़िया, एपीओ प्रथम अमित कुमार मीणा व पीओ द्वितीय मागे राम तथा पीओ तृतीय रतनसिंह को मतदान केंद्र की गोपनीयता भंग करने पर नोटिस जारी किया है। गौतम ने नोटिस में कहा है कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र के लिए छह मई को हुए मतदान के दौरान बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 173 पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी अर्जुनराम मेघवाल जब मतदान हेतु उपस्थित हुए तो उनके साथ एक पुलिस कर्मी एवं अन्य एक व्यक्ति भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित था एवं उस अन्य व्यक्ति के पास स्मार्ट फोन भी था, जिससे उसके लाइव वीडियो क्लिप बनाई गई। गौतम ने कहा कि निर्वाचन संचालन नियम 1961 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानानुसार मतदान केन्द्र पर मतदाता के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र पर प्रवेश नहीं कर सकता, जिससे मतदान की गोपनीयता बनी रहे सके। इस बारे में मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी गई थी और पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका भी दी गई थी, जिसमें निर्देशों की जानकारी थी।

तमिलनाडु में 13 मतदान केंद्रों पर 19 मई को पुनर्मतदान

नई दिल्ली (आरएनएस)। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के पांच संसदीय क्षेत्रों के 13 मतदान केंद्रों पर 19 मई को पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। आयोग ने एक बयान में यह जानकारी दी। तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को भेजे गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने 18 अप्रैल को धर्मपुरी में आठ मतदान केंद्रों पर, तिरुवल्लूर में एक, कुड्डालोर में एक, एरोड में एक और थेनी में दो मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को अमान्य घोषित कर दिया है। ये 13 मतदान केंद्र पूनामाली, पप्पीरेड्डीपट्टी, पनरुति, कांगेयम, अंडीपट्टी और पेरियाकुलम विधानसभाओं में भी आते हैं जहां 19 मई को उपचुनाव होने हैं। प्रदेश के 13 जिलों के 46 बूथों पर गड़बड़ियों की सूचना मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग ने सीईओ को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पुनर्मतदान की जानकारी देने के लिए और क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार करने के लिए कहा है।

समान कार्य समान वेतन पर बिहार के लाखों शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

नई दिल्ली (आरएनएस)। बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार की अपील मंजूर कर ली है और पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 11 याचिकाओं पर सुनवाई की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब से ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लाखों नियोजक शिक्षकों को बेसब्री से इंतजार था। बिहार के 3 लाख 56 हजार टीचर्स की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से लगी हुई थीं। बिहार में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। पहले इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था और बिहार सरकार को समान वेतन देने का निर्देश दिया था। हालांकि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने से पहले याचिका पर सुनवाई की थी। शिक्षक संघ की तरफ से अधिवक्ता ने कहा था कि पटना हाई कोर्ट ने समान काम-समान वेतन के पक्ष में सही फैसला दिया है। सरकार फैसले को लागू नहीं कर बेवजह नियोजित शिक्षकों को परेशान कर रही है। शिक्षक संघ की ओर से कोर्ट में तर्क दिया जा रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन, नियोजित शिक्षकों का मौलिक अधिकार है। वहीं, केंद्र सरकार नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने के लिए राशि बढ़ाने पर सहमत नहीं दिखी थी। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति और वेतन देना राज्य सरकार का काम है। इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र ने तर्क दिया था कि नियमित शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से हुई है।

प्रियंका 13 को रतलाम-इंदौर में चुनावी सभा लेंगी

भोपाल (आरएनएस)। कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी सोमवार 13 मई 2019 को प्रदेश के दौरे पर रहेंगी, यहां वे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के उपरांत, रतलाम में जनसभा को संबोधित करेंगी। उसी दिन शाम को इंदौर में वे कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रोड-शो में रहेंगी। प्रदेश मीडिया प्रमुख शोभा ओझा ने बताया कि प्रियंका गांधी 12.40 बजे इंदौर से हेलिकॉप्टर द्वारा उज्जैन पहुंचेंगी, तत्पश्चात 1.15 बजे उज्जैन से महाकालेश्वर दर्शन, 2.00 बजे रतलाम और 2.30 बजे रतलाम में जनसभा को संबोधित करेंगी। उसके बाद 3.40 बजे हेलिकॉप्टर द्वारा रतलाम से इंदौर तथा 4.30 बजे इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो में शामिल होंगी।

राफेल डील: सुको के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर 14 दिसंबर 2018 को दिए अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में भी राफेल का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि दिसंबर में सु्र ने अपने फैसले में फ्रेंच कंपनी दसॉ से 36 फुली लोडेड राफेल जेट्स खरीदने के मामले में एनडीए सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले वकील प्रशांत भूषण ने तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और मामले की आपराधिक जांच शुरू होनी चाहिए। ब्क्क से कथिततौर पर समानांतर बातचीत से संबंधित दस्तावेजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय वार्ताकारों की टीम के तीन सदस्यों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध हुआ है। शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि राफेल डील की प्राइसिंग इंटर-गवर्नमेंट अग्रीमेंट के आर्टिकल 10 के तहत कवर्ड है और इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और दुनिया की कोई भी कोर्ट इस तरह के तर्कों पर डिफेंस डील की जांच नहीं करेगी। राफेल मामले में पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि राफेल डील के लिए जो प्रक्रिया चल रही थी, उसे पीएमओ द्वारा मॉनिटर करना पैरलल निगोशिएशन (सामानांतर बातचीत) या दखल नहीं कहा जा सकता है।

फिर टली अयोध्या मामले की सुनवाई, मध्यस्थता के लिए मिला तीन महीने का समय

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या में श्रीराम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तीन महीने के लिए फिर टल गई है। इस मामले पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस एफएमआई खलीफुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 अगस्त तक का समय मांगा गया। इस पर विचार करते हुए कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता का समय 15 अगस्त तक बढ़ा दिया। इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, हम मामले में मध्यस्थता कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इसको गोपनीय रहने दिया जाए। इस दौरान वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा, हम कोर्ट के बाहर बातचीत से समस्या के हल निकालने का समर्थन करते हैं। साथ ही मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की ओर से अनुवाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनुवाद में कई गलतियां हैं। पांच वक्त नमाज और जुमा नमाज को लेकर गलतफहमी है। इसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को अपनी आपत्तियों को लिखित में दाखिल करने की इजाजत दे दी। अयोध्या मामले में अभी 13 हजार 500 पेज का अनुवाद किया जाना बाकी है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर की संवैधानिक बेंच कर रही है। अब 15 अगस्त के बाद ही पता चलेगा कि मध्यस्थता प्रक्रिया ने क्या हासिल किया, क्योंकि अदालत ने आदेश दिया था कि प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होनी चाहिए। इससे पहले 8 मार्च को अयोध्या की भूमि पर मालिकाना हक के मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की इजाजत दी थी। मध्यस्थों की कमेटी में जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला, वकील श्रीराम पंचू और आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर शामिल हैं।

सेना व आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आईएसजेके कमांडर इशफाक सोफी ढेर

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ की खबर है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर (आईएसजेके) के कमांडर इशफाक अहमद सोफी को मार गिराया है। बता दें कि जाकिर मूसा के अलावा इशफाक अहमद सोफी कश्मीर में आईएसजेके का बड़ा कमांडर था। जाकिर मूसा अभी भी सुरक्षबलों की पकड़ से दूर है। पिछले दिनों उसके पंजाब में छुपे होने की खुफिया रिपोर्ट आई थी। इशफाक अहमद सोफी जम्मू-कश्मीर के सोपोर का रहने वाला था। उसको एनकाउंटर के दौरान जम्मू-कश्मीर के शोपियां में मार गिराया गया। आईएसजेके आतंकी इशफाक अहमद सोफी को अब्दुल्ला भाई के नाम से भी जाना जाता था। उसके पास से आर्म्स और एम्युनिशन बरामद हुए हैं। वहीं, आतंकी इशफाक अहमद सोफी के मारे जाने के बाद सोपोर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने इलाके के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सोपोर के अमशिपोरा में शुक्रवार तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान मारा गया। इशफाक अहमद सोफी कश्मीर में आतंकी संगठन आईएसजेके का बड़ा कमांडर था। वह साल 2015 में हरकत-उल-मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा था।

आजमगढ़ में अखिलेश की 4 जनसभाएं रद्द

» सपा ने प्रशासन पर लगाए आरोप

लखनऊ (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण के प्रचार के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी (सपा) को झटका लगा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सगड़ी, आजमगढ़ सदर, गोपालपुर, व मेहनगर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली 4 सभाओं को रद्द कर दिया गया है। सभाएं रद्द होने पर समाजवादी पार्टी ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आजमगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा, सभी जानते हैं कि आजमगढ़ गठबंधन को हमेशा जीत मिलती है। उन्होंने कहा, हार की हताशा व सत्ता के दबाव में निर्वाचन से जुड़ी संस्थाएं खासतौर से जिला प्रशासन तकनीकी दृष्टि से चुनाव को रद्द करने का बहाना ढूंढ रहा है। इसीलिए प्रचार समाप्त होने में दो दिन शेष रहते चुनाव मद में होने वाले खर्च की पूर्व निर्धारित दरों को संशोधित कर दिया गया है।यादव ने आशंका जताते हुए कहा कि सत्ता व प्रशासन की दुरभि संधि के चलते 10 मई को सपा अध्यक्ष व लोकसभा प्रत्याशी अखिलेश यादव के आजमगढ़ में प्रस्तावित जनसभाओं को निरस्त कर दिया गया है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी (डीएम) शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से अखिलेश यादव की कोई सभा रद्द नहीं की गई है। चुनाव आयोग की ओर से खर्चे पर निगरानी रखने वाले व्यय पर्यवेक्षक की ओर से सभी पार्टियों को खर्चे को लेकर नोटिस भेजा गया है। उन्होंने अपनी सभाएं खुद ही रद्द की हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कहा, चुनाव खर्च की दरों में संशोधन जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का विषय है।

एक बार फिर भारत के सामने हाथ फैलाने मजबूर है पाक

नई दिल्ली (आरएनएस)। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बने हुए है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट-फेवर्ड नैशन का दर्जा वापस ले लिया था। वहीं अब देखें तो दोनों देशों के मध्य व्यापारिक रिश्ते भी बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अब पाकिस्तान को भारत की चाय ही पीनी पड़ सकती है, क्योंकि चार के बड़े उत्पादक देश केन्या में इस साल सूखा पड़ने की वजह से उत्पादन घट गया है। ऐसे में केन्या से चाय मंगाना पाकिस्तान के लिए बेहद महंगा होगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से चाय खरीदने के लिए बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के लिए भारत के चाय पड़ेगी सस्ती। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष पाकिस्तान को लगभग 1.58 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया था। लेकिन मौजूदा समय में पाकिस्तान के ऊपर 200 फीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए भारत के चाय सस्ती पड़ेगी। लिहाजा भारत चाय का निर्यात 2019 में बढ़कर 2-2.5 करोड़ किलोग्राम हो सकता है।